Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

दैनिक

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्षः 2 अंकः 210 , 05 जनवरी, शुक्रवार 2018, सूरत, हिन्दी दैनिक मो. 9879141480

4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

हवाई अड्डे पर यात्री के सामान से मिला कारतूस

नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन के चेक इन एरिया में जांच के दौरान डायल के सुरक्षाकर्मी ने यात्री बसंत प्रसाद के पास से 7.66 एमएम का कारतूस जब्त किया। डायल ने यात्री बसंत प्रसाद को एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया है। दिल्ली निवासी बसंत प्रसाद 2 जनवरी की रात 23.20 बजे फ्लाइट नंबर 9 डब्ल्यू 304 से मुंबई जाने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे थे। पुलिस ने एयरपोर्ट पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

समितियों ने पेश किए संशोधित बजट

पूर्वी दिल्ली। राजधानी में 19 से 30 जनवरी तक होने वाली आसियान बैठक की तैयारियों को लेकर महापौर नीमा भगत ने बुधवार को अक्षरधाम से निजामुद्दीन क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर स्थायी समिति अध्यक्ष प्रवेश शर्मा, सदन नेता संतोष पाल, पार्षद गोविंद अग्रवाल, निगमायुक्त डॉ. रणवीर सिंह आदि मौजूद थे। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि आसियान बैठक में विभिन्न 10 देशों से आने वाले गण्यमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र का व्यवस्थित, स्वच्छ होना जरूरी है। उन्होंने अक्षरधाम से निजामुद्दीन जाने वाले रास्ते का निरीक्षण कर वहां सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने अक्षरधाम से निजामुद्दीन की ओर जाने वाली सड़क के सभी यूनीपोलों में सभी राष्ट्राध्यक्षों की फोटो लगाने को कहा। इस मौके पर उन्होंने निर्माण कायरें को जल्द पूरा और धूल फैलाने वाली सभी इकाइयों के चालान किए जाने की बात कही। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में विभिन्न समितियों के अध्यक्षों ने संशोधित बजट पेश किया। बजट से संबंधित दिए गए विभिन्न समितियों के सुझाव के अनुरूप अध्यक्ष ने पेश किए गए बजट में जरूरी संशोधन किया। स्थायी समिति सदस्यों द्वारा चर्चा करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष ने निगम की आय बढ़ाने व कई मदों में कर बढ़ाने के भी सुझाव दिए।

अस्पताल के बाउंसरों पर मारपीट का आरोप

नई दिल्ली। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज कराने गए मरीज ने अस्पताल के बाउंसरों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित की पहचान राहुल के तौर पर हुई है। अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़ित के खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद पीड़ित ने बाउंसरों के खिलाफ थाना हरिदासनगर में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहुल परिवार के साथ तिहाड़ गांव में रहता है। उसका आरोप है कि 28 दिसम्बर की रात पेट में दर्द होने पर दूसरे दिन सुबह चार-पांच बजे के करीब वह अपने दोस्त राजू के साथ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल गया था। जब काफी देर तक उसका उपचार नहीं हुआ तो उसने वहां मौजूद एक बाउंसर से जल्द उपचार करवाने को कहा। यह कहते ही बाउंसर राहुल को घसीटता हुआ ड्रेसिंग रूम में ले गया, जहां पर चार बाउसर पहले से ही मौजूद थे। यहां सभी ने मिलकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। वहां मौजूद डाक्टरों ने उसका न तो उपचार किया और न ही बचाने की कोशिश की। उल्टा पुलिस को सूचना दे बदतमीजी करने का आरोप लगाकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। 29 दिसम्बर को मोतीनगर अदालत से दोनों को जमानत मिल गई।

पीसीआरकर्मी पर लात घूसों से हमला

पूर्वी दिल्ली। थाना आनंद विहार क्षेत्र में दो शराबियों ने थाने में हेड कांस्टेबल को घूसा मारकर घायल कर दिया, जिससे पीड़ित विरेन्द्र (43) की आंख पर गंभीर चोटों के अलावा माथा भी फट गया। इतना ही नहीं दोनों ने पीड़ित पर लात-घूंसे से भी हमला कर दिया। विरेन्द्र की चिल्लाने की आवाज सुनकर आए अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे छुड़ाकर किसी तरह दोनों को काबू किया।

घायल विरेन्द्र को डॉ. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों सोनम दोरजी (22) व प्रेम शेरिंग (23) को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंगलवार तड़के 4.30 बजे के करीब सूचना मिली कि सीबीडी ग्राउंड के पास होटल लीला के बाहर नशे में धुत्त दो युवक झगड़ा कर रहे हैं।

आजमगढ़ में बोले सीएम योगी,

प्रदेश के 20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

आजमगढ़ (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले 4 वर्षों में सूबे के 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 21 व 22 फरवरी को लखनऊ में दुनिया भर के निवेशकों का एक सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें निवेशक यूपी में 5 लाख करोड़ रुपया निवेश करने पर सहमति बनेगी। यह निवेश क्रमश चार वर्षों में होगा। उन्होंने सठियांव चीनी मिल स्थित डिस्टलरी प्लांट समेत साढ़े 5 अरब की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास के दौरान ये बातें कहीं। इस दौरान भ्रष्टाचार पर वह फिर सख्त दिखे। सीएम योगी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों से सरकार गुंडों और बदमाशों की तर्ज पर निपटेगी। सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के बीच मे गोलमाल नहीं चलेगा। खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होगा। गरीब का हक मारने वाले अफसरों, माफियाओं की सम्पत्ति जब्त कर गरीबो में बांट दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि सूबे में किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पिपराइच, बस्ती चीनी मिल के बाद जल्द ही 3 अन्य चीनी मिलें किसानों की तरक्की के लिए चालू हो जाएगी। अब हमारा किसान युवा रोजगार के लिए दूसरे देश नही जाएगा। उसे अपने घर मे रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिभा का सम्मान होगा। कुल डेढ़ लाख पुलिस की भर्ती पारदर्शी तरीके से की जाएगी। वैसे ही 1.38 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश की आद्योगिक ढांचे को विकसित करने के लिए आने वाले 4 वर्षों में 5 लाख करोड़ का निवेश सूबे में होगा। इसके लिए 21 फरवरी को लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन निवेशकों का होने जा रहा है। इससे 20 लाख युवाओ को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा, वन मंत्री दारा चौहान भी मौजूद थे।

गुजारे लायक नहीं मिली पेंशन तो करेंगे सांसदों-विधायकों का घेराव

नई दिल्ली (एजेंसी)। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के सदस्यों ने कम से कम 7,500 रु पये पेंशन मासिक पेंशन और अंतरिम राहत के रूप में पांच हजार रु पए महंगाई भत्ते की मांग के लिए अपना आंदोलन तेज कर दिया है। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी देश भर के 500 जिलों में लोकसभा सांसदों और विधायकों का घेराव करेंगे। उनके आवास पर धरना देंगे और सत्याग्रह करेंगे। अशोक राउत ने कहा कि इस दौरान इन सांसदों और विधायकों पर ईपीएस पेंशनरों को हो रही परेशानी पर पीएम को पत्र लिखने के लिए भी दबाव बनाया जाएगा। इसके लिए जनसाधारण से लेकर कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों से भिक्षा ली जाएगी। एकत्र भिक्षा जिला कलक्टर, एसडीएम, तहसीलदार के माध्यम से डीडी, पोस्टल ऑर्डर या नकद के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में भेजी जाएगी। आपने तो हमारी बात नहीं सुनी, पर हम अपने सीमित संसाधनों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अपना योगदान दे रहे हैं। पेंशन कम, कैसे चले खर्च : इस समय ईपीएस-95 से हर महीने इसके सदस्यों को कम से कम एक हजार रु पये महीने पेंशन मिलती है। लाखो पेंशनरो को तो उससे भी कम पेंशन मिलती है। अशोक राउत के अनुसार ईपीएस-95 योजना के तहत 60 लाख पेंशनधारक है जिसमें से करीब 40 लाख सदस्यों को 1500 रु पये से कम पेंशन मिल रही है और अन्य कर्मचारियों को दो हजार रुपये से ढाई हजार रुपये मासिक पेंशन मिल रही है।

पेंशनरों की मुख्य मांगें : ईपीएफराष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि सरकार से हमारी मांग है कि वह कम से कम 7500 रु पए मासिक पेंशन, अंतरिम राहत के रूप में 5000 रु पए महंगाई भत्ते की मांग कर रहे है।

कानपुर की खुशी बनना चाहती है मिनी माइकल जैक्सन

कानपुर दक्षिण (एजेंसी)। मंजिल दूर है और सफर बहुत है। छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। हर मुसीबत को फतह करूंगी, क्योंकि पापा के प्यार में असर बहुत है। यह कहना है, बर्रा विश्वबैंक में रहनेवाली खुशी सक्सेना का।

कक्षा चार में पढ़नेवाली आठ वर्षीय खुशी छोटी सी उम्र में डांस के कई राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपने हुनर का लोहा मनवा चुकी है। हाल में ही दिल्ली में हुए जस्ट डांस इंडिया सीजन-2 की फर्स्ट रनर अप और बड़ोदरा में आयोजित रियलिटी शो जम के नाच में थर्ड राउंड क्वालीफाई किया है। खुशी अपनी इस सफलता का श्रेय पापा शिव शंकर को देती है। खुशी डांस की दुनिया में माइकल जैक्सन की तरह नाम कमाना चाहती है। यही पापा का सपना भी है। स्कूल और आसपास के लोग उसे मिनी एमजे (माइकल जैक्सन) के नाम से पुकारते हैं, यह नाम ही खुशी की पहचान भी है। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए खुशी दिन में पांच घंटे प्रैक्टिस करती है, जिनमें डेढ़ घंटे ए वायरस डांस स्टूडियो की क्लास भी शामिल है।

पिता का सपना पूरा करने की ठानी

ट्रैवेल्स का काम करनेवाले शिवशंकर का सपना एक बड़ा डांसर बनने का रहा। शुरुआती दिनों में उन्होंने शहर के कई छोटे स्टेज पर हुनर से वाहवाही लूटी। आर्थिक तंगी के चलते मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। एक प्राइवेट स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी की और घर पर डांस क्लासेज चलाते रहे। अब ट्रैवेल्स का कारोबार कर घर चला रहे हैं। पहली बेटी (खुशी) होने पर शिवशंकर ने उसे डांस के शिखर तक पहुंचाने का प्रण किया। बेटी जब ढाई साल की थी, तभी से गुरु बनकर डांस सिखाना शुरू कर दिया। उम्र बढ़ने के साथ बेटी पापा के सपनों पर खरी उतरती गई। अब बेटी ने भी पापा के सपने को पूरा करने के लिए हर मुश्किल को फतह करने की ठान ली है।

ऑनलाइन रियलिटी शो में जलवा

जस्ट डांस इंडिया यू-ट्यूब का सबसे बड़ा ऑनलाइन रियलटी शो है, जिसमें देशभर के करीब चार हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। जूनियर वर्ग (पांच से 14 वर्ष) के करीब एक हजार बच्चों में खुशी फर्स्ट रनर अप रही। अब खुशी पांच जनवरी को लखनऊ में होनेवाले डांस इंडिया डांस लिटिल चैम्प के ऑडिशन की तैयारी कर रही है।

अब तक की कामयाबी का सफर

2016 : ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप विजेता (जबलपुर)

2017 : यूथ वार डांस कम्पटीशन फर्स्ट रनर अप (कानपुर)

2017 : सुपर डांसर सीजन-2 थर्ड राउंड (दिल्ली)

2017 : ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप सेकेंड रनर अप (जयपुर)

2017 : जस्ट डांस इंडिया सीजन-2 फर्स्ट रनर अप (दिल्ली)

2017 : जम के नाच थर्ड राउंड क्वालीफाई (बड़ोदरा)

2017 : यूपी डांसिंग चैंपियनशिप विजेता (कानपुर)

हलफनामा देने के बाद ही बैठक में शामिल होने की मिली अनुमति

बैठक में निष्कासित पार्षदों का हंगामा ईडीएमसी की बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की बैठक शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के 11 निष्कासित पार्षदों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। निष्कासित पार्षद बैठक में शामिल करने की मांग कर रहे थे। आखिर में मेयर कमलजीत सहरावत ने पार्षदों से हलफनामा लिखवाकर बैठक में शामिल होने अनुमति दे दी। हालांकि आप के पार्षदों के हंगामे की वजह से मेयर को 15 मिनट के लिए बैठक स्थिगत करनी पड़ी। बैठक शुरू होने से पहले ही सभी निष्कासित पार्षद अंदर घुस आये। हालांकि मार्शलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। बैठक परिसर में घुसकर हंगामा करने लगे। जैसे ही मेयर पहुंची, विपक्ष के सभी पार्षद बेल में आ गये और हंगामा करने लगे। विपक्ष के पार्षदों का तर्क था कि न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है। इसलिए उन्हें बैठक में शामिल किया जायेगा। करीब 15 मिनट तक हंगामा चलता रहा। बाद में मेयर ने उन्हें आस्त किया कि यदि वह लिखकर दे दें कि अब हंगामा नहीं करेंगे, तो वह बैठक में शामिल होने की अनुमति दे सकती हैं। इस पर सभी पार्षद तैयार हो गये। मेयर ने उन्हें समय देकर 15 मिनट के लिए बैठक स्थिगित कर दी। मेयर के लौटने पर अपने पार्षदों को तरफसे नेता विपक्ष ने मेयर को लिखकर दे दिया। इसके बाद बैठक शुरु हुई।पार्षदों की नोंक-झोंक पर मुस्कुराते रहे अधिकारी : बैठक स्थिगित कर मेयर अपने कार्यालय में चली गयीं। इस बीच पक्ष एवं विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर नोंक-झोंक हुई। विपक्ष की एक महिला पार्षद ने खड़े होकर सत्तापक्ष के पार्षदों पर टीका टिप्पणी शुरु कर दी। इसको लेकर दोनों तरफसे टीका-टिप्पणी शुरू हो गयी।

क्यों टूटा कुमार से भरोसा?

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएसी की बैठक में आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सीट का टिकट मिलने की उम्मीद करने वालों में शामिल आशुतोष ने अरवपति कारोबारी के नामांकन पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कौन है यह गुप्ता, कहा से आया है । नौ पीएसी सदस्यों में आशुतोष आपत्ति उठाने वाले एकमात्र सदस्य थे। आप के संस्थापक सदस्यों में से एक कुमार विस आज नैपथ्य में चले गए। महज पांच साल के भीतर आखिरकार क्या हुआ कि केजरीवाल का कुमार विस पर से विस उठ गया और आज वह अकेले हो गए? भाजपा के कुछ नेताओं के साथ उनके निजी रिश्ते उनके लिए नासूर बन गया।कुमार को साइड लाइन करने के लिए पार्टी के भीतर सियासी गोटियां बिछायी गईं। कुमार की बढ़ती लोकप्रियता भी सियासी डगर पर कांटे की तरह कुछ लोगों को चुभने लगी। कुमार की लोकप्रियता का आलम यह है कि हर पार्टी में उनके फालोवर हैं। खासकर भाजपा में। मुकेश अंबानी से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी निजी रिश्ते हैं। प्रशांत भूषण को निकाले जाने के बाद कुमार ही पार्टी के असल निशाने पर रहे हैं।

पंजाब विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के समय कुमार ने सवाल उठाए थे। इसलिए उनका नाम पंजाब चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची से काट दिया गया। ईवीएम को लेकर आप ने सवाल उठाए तो कुमार ने पार्टी लाइन से इतर ट्वीट किया। उसी के बाद दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना था। आप दिल्ली नगर निगम चुनाव में बुरी तरह से हार गई। हालांकि निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। फिर भी निगम चुनाव में हार का ठीकरा कुमार पर फोड़ दिया गया। कहा गया कि कुमार के एक ट्वीट ने पार्टी को हराने का काम कर दिया। कपिल मिश्रा को लेकर कुमार विस का साफ्ट कार्नर रहा है। बताया जाता है कि कपिल मिश्रा कुमार के खास आदमी है। पार्टी ने पहले कपिल को निपटाकर कुमार को साफ संकेत दे दिया कि वे संभल जाएं। इससे पूर्व ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान ने कुमार को आरएसएस का एजेंट कहा। कुमार आग-बबूला हो गए।

पार्टी ने कुमार के दुखती रग पर मरहम लगाते हुए अमानतुल्ला को सस्पेंड किया और कुमार को राजस्थान का प्रभारी बना दिया। कुमार खुश हो गए। अमानतुल्ला को कुछ ही दिनों में वापस ले लिया गया और कई अहम जिम्मेदारियां दे दी गईं। कुमार देखते ही रह गए। इस बीच कुमार समय-समय से कुछ ट्वीट करते रहे और पार्टी को बैकफुट पर धकेलते रहे। जिसको देखते हुए कुमार संदिग्ध होते गए। पार्टी के कुछ लोग कुमार को भाजपा का एजेंट बनाने की साजिश रचते रहे। बहरहाल इस समय कुमार न भाजपा के हैं और न आप के। कुमार ने स्पष्ट किया है कि अब वह साहित्य रचना में ध्यान देंगे। अपनी रचनाधर्मिता को आगे बढ़ाएंगे।

कलम की स्याही और मन के भाव तो सांसों के साथ ही होंगे खत्म-गोपालदास नीरज

अलीगढ़ (एजेंसी)। गोपालदास नीरज...कवि नहीं, चलता-फिरता महाकाव्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उम्र के जिस पड़ाव को जीवन की संध्या कहा जाता है, नीरज उस उम्र में भी रोज कुछ नया रच रहे हैं...गुरुवार को वह अपना 93वां जन्मदिन मनाएंगे। जिन्हें भी यह लगता है कि नीरज बूढ़े हो गए हैं, उम्र हो चली है, अब शरीर साथ नहीं देता...उन सबको वह अपने अंदाज में जवाब देते हैं कि, 'आत्मा के सौंदर्य का शब्दरूप है काव्य...मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य...।' नीरज आज भी लिख रहे हैं और कहते हैं कि उनके कलम की स्याही और मन के भाव तो सांसों के साथ ही खत्म होंगे। अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 'आंचल अवस्थी' से हुई बातचीत में नीरज ने पूरे हो चुके सपनों से लेकर अधूरी ख्वाहिशों तक के बारे में बात की और नई रचनाएं सुनाकर यह भी जता दिया कि अभी तो उनमें बहुत सारा काव्य बाकी है...

76 बरस बीत गए लिखते-लिखते...

गोपालदास नीरज की जितनी उम्र है, उसमें तीन चौथाई हिस्सा तो उनके अनुभवों का है। उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था और आज तक लिख रहे हैं। 76 बरस बीत गए लिखते-लिखते... इतने लम्बे अरसे को युग कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इस दौरान नीरज काव्य मंचों से लेकर फिल्मी गीतों की दुनिया तक का सबसे बड़ा नाम बने। फिल्म 'जोकर' के गीत 'ए भाई जरा देख के चलो...' से पहचान मिली और उसके बाद 60-70 के दशक में रोमांटिक गीतों का दूसरा नाम 'नीरज' हो गए। लगभग एक साल पहले तक कवि सम्मेलनों में मंचों पर नीरज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, हालांकि अब स्वास्थ्य कारणों से मंचों पर जाना बेहद कम हो गया, हालांकि काव्य सृजन आज भी जारी है।

60 का दशक सबसे खूबसूरत

नीरज जब गुजरे दौर के पन्ने पलटते हैं तो उन्हें 60 का दशक जरूर याद आता है। कहते हैं, ये बड़ा सुनहरा वक्त था। बच्चन जी को सुनकर उन्होंने लिखना सीखा था और उनके साथ काव्य मंचों पर जाना नीरज के लिए किसी सौभाग्य से दशकों में काव्यमंच बिजनेस का जरिया बन गए।

कारवां गुजर गया...जीवन की सच्चाई-

नीरज ने सैकड़ों गीत लिखे और उन गीतों का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। मगर अपने लिखे जिन गीतों को वह अपने सबसे करीब पाते हैं, उनमें 'कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे...' और 'ए भाई जरा देख के चलो...' हैं। नीरज कहते हैं कि इन दोनों में जीवन दर्शन छिपा है।

खुली किताब हूं, आत्मकथा क्यों लिखूं-

नीरज का व्यक्तिगत जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। मगर जब यह कहानी लिखने की बात आती है तो वह सिरे से खारिज कर देते हैं। आत्मकथा लिखने के सवाल पर वह कहते हैं मैं खुली किताब हूं, लोग मेरे बारे में सब जानते हैं तो आत्मकथा लिखने की जरूरत क्या है।

आजकल लिख रहे हैं हाइकू और दोहे-

नीरज आजकल ज्यादा वक्त अलीगढ़

में बिताते हैं। वहां रहकर वह हाइकू और दोहे लिख रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने फोन पर ही कुछ हाइकू सुना दिए... 'वो हैं अकेले
दूर होके खड़े
देखे जो मेले।'
'वो है निराला
जिसने पिया सदा
विष का प्याला।'

अनवर जलालपुरी का जाना दिल तोड़ने जैसा...

दो दिन पहले जाने-माने शायर अनवर जलालपुरी का इंतकाल हुआ, जिससे पूरा काव्यजगत सदमे में है। नीरज भी इस गम से अछूते नहीं हैं, वजह भी वाजिब है क्योंकि नीरज और अनवर का साथ तकरीबन 40 साल पुराना था। अनवर जलालपुरी के जिक्र पर नीरज के दिल से आह कुछ यूं निकलती है... 'महाठगन ये सांस है, पल-पल आए जाए, रुक जाएगी कब कहां, कोई जान न पाए...

जो संस्कृति महान होती है वह दूसरों की संस्कृति को भय नहीं देती, बल्कि उसे साथ लेकर पवित्रता देती है। गंगा महान क्यों है? दूसरे प्रवाहों को अपने में मिला लेने के कारण ही वह पवित्र रहती है -साने गुरु

दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक

भड़की हिंसा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है। प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। उम्मीद करनी चाहिए कि हिंसा के पीछे का सच सामने आ जाएगा। किंतु पूरे प्रकरण को देखने से लगता है कि यह हिंसा अपने-आप पैदा नहीं हुई है। कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की जिससे टकराव की नौबत आए और फिर उसे बढ़ावा भी दिया। 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की पराजय हुई जिससे मराठा राज का अंत हुआ। इस युद्ध में स्थानीय महार अंग्रेजों के पक्ष में लड़े थे। पिछले कई दशकों से दलितों का एक वर्ग उसे शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। दलितों के साथ जितना अमानवीय व्यवहार उस दौरान होता था उसमें उनके अंदर पेशवा शासन के खिलाफ गुस्सा स्वाभाविक था। आज उसे शौर्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए या नहीं इस पर निश्चित तौर पर दो राय हो सकती है। किंतु 1 जनवरी 2018 उस युद्ध की 200 वीं बरसी थी। उसे बड़े पैमाने पर मनाने की योजना कुछ संगठनों ने बनाई थी। वहां के कार्यक्रम में जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद आदि ने जिस तरह का भाषण दिया उससे दूसरे वर्ग में उत्तेजना पैदा हुई थी। पहली नजर में यह प्रशासन की विफलता दिखाई देती है जिसने स्थिति को संभालने का पर्याप्त पूर्वोपाय नहीं किया। किंतु विचार करने वाली बात है कि आखिर कोरेगांव भीमा में हुई मारपीट कैसे प्रदेश के अन्य जिलों में हिंसा में परिणत हो गया? उसके बाद प्रदेश बंद का भी आह्वान हो गया और हमने देखा कि उस दौरान किस तरह की हिंसा होती रही। निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को जिस पैमाने पर क्षति पहुंचाई गई उसके पीछे निश्चय ही ऐसे तत्वों की भूमिका होगी जो प्रदेश में जातीय तनाव भड़काए रखना चाहते हैं। लोगों से शांति की अपील करने या अपनी पार्टी को शांति स्थापना के लिए काम करने का निर्देश देने की जगह केवल आरोप लगाए। ऐसे समय, जब किसी कारण से भी तनाव भड़का हो, एक-एक दल और संगठन का दायित्व बनता है उसे रोकने का। सियासी मोर्चाबंदी तो बाद में भी हो सकती है। तो पूरा दारोमदार प्रदेश सरकार एवं स्थानीय लोगों पर ही जाकर टिकता है। सरकार हिंसा रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाए तथा स्थानीय लोग यह समझें कि शांति और सद्भाव में ही सबका भला है। अपील है कि दलित एवं मराठा समुदाय के विवेकशील लोग आगे आएं और तनाव को दूर करने की पहल करें।

चुनावी फंडिंग

सरकार ने बीते मंगलवार को चुनावी बांड योजना की विस्तृत रूपरेखा जारी करके चुनावी फंडिंग को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान संसद में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। सरकार दावा कर रही है कि यह योजना राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकदी चंदे के प्रचलन को हतोत्साहित करेगी और इस तरह चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लग पाएगी। अब आगामी चुनावों में सरकार के दावे की असलियत का पता चल पाएगा। फिर भी, आशावादी नजरिये से यह तो कहा ही जा सकता है कि पूरी तरह तो नहीं लेकिन एक सीमा तक काले धन के इस्तेमाल को रोकने में यह योजना कारगर हो सकती है। इस योजना के मुताबिक, राजनीतिक दलों के लिए एक हजार से लेकर एक करोड़ रुपये के मूल्य तक के चुनावी बांड एसबीआई बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीदे जा सकेंगे और इसकी मियाद पंद्रह दिनों की होगी अर्थात इन्हें केवल अधिकृत बैंक खातों के जरिए इस मियाद के भीतर भुनाना होगा। चुनावी बांड लेने की कुछ अर्हताएं भी निर्धारित की गई हैं। मसलन, राजनीतिक दल का पंजीकरण और पिछले चुनाव में कम से कम एक फीसद वोट पाना अनिवार्य है। चुनाव के मौसम में काले धन को सफेद करने के इरादे से कुकुरमुत्ते की तरह उग आने वाली नईराजनीतिक पार्टियों को ये चुनावी बांड नहीं दिए जा सकेंगे। सरकार के इस कदम को चुनाव सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। राजनीतिक दल विश्वसनीय नहीं होते और लोकतंत्रकी प्रक्रिया को पीछे धकेलते हैं। अलबत्ता, चुनावी बांड में दानदाता के नाम को गोपनीय रखने का प्रावधान राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य को धूमिल करता है। दानकर्ता को अपनी बैलेंस शीट में चुनाव बांड का जिक्र करना होगा लेकिन सवाल यह है कि आम जनता को कैसे पता चल पाएगा कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना चुनावी चंदा दिया? इस नजरिये से राजनीतिक फंडिंग पारदर्शी बनाने का मकसद आधा-अधूरा ही रह जाता है।

सत्संग

दान की महिमा

जिन लोगों के कारण इस धरा पर सतयुगी परिस्थितियां बनी हुई थीं, उन्हें भूसुर अर्थात धरती का देवता कहा जाता था। ये भूसुर कहीं आसमान से नहीं टपकते थे , बल्कि इसके पीछे इनके जीवन जीने की श्रेष्ठ शैली ही थी। उनकी श्रेष्ठता का मूल आधार हुआ करता था- परमार्थ। वे अपने आपको समाज के लिए समर्पित कर देते थे। आखिर परमार्थ है क्या? हमारी मोटी बुद्धि दान को ही परमार्थ मानती है। साधारण जन तो दान का मतलब सीधे धन दान से ही लगाते हैं। लोग इस परिभाषा को इसलिए कबूल करते हैं कि इसमें एक का धन दूसरे के हाथ में, बदले में कुछ लिए बिना जाता हुआ सामने दिखाई देता है। इस प्रक्रिया में देखने वाला उसे उदार, दानवीर, पुण्यात्मा आदि मानता है। यह शोहरत उसे हाथों-हाथ मिलती है , जिसे वह धन मिला है, वह तो प्रशंसा करता ही है। वह अन्य तमाम लोगों से चर्चा करके उसकी यश-पताका फहराता फिरता है। दान के रूप में दिया गया धन यदि कहीं कुपात्र के हाथ लगा, तो जाहिर है उसे वह दुर्व्यसनों में ही खर्च करेगा। जो धन पसीना बहाकर कमाया नहीं गया, उसका सदुपयोग होना संदिग्ध ही है। इस प्रकार दान करने वाला व्यक्ति यदि अपना धन सत्पात्र के बजाय किसी कुपात्र को देता है, तो पुण्य के स्थान पर पाप ही बढ़ाता है। बिना श्रम किए पैसा पाकर दुर्गुणी व्यक्ति की प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्तियों की ओर ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार अविवेकपूर्वक दिया गया, धूर्त और पाखंडियों को दिया हुआ दान, दानवीर के लिए भी अवगति का कारण बनता है। आपत्ति में डूबे हुए लोगों की मदद करना तो अच्छी बात है, किंतु देने वालों को देखना यह भी चाहिए कि सस्ती वाहवाही के फेर में कहीं वे लेने वाले का स्वाभिमान और स्वावलंबन तो नहीं नष्ट कर रहे हैं। गांधीजी की बहन विधवा थीं। उसकी पुत्री भी विधवा हो गई। उसने गांधीजी से कुछ सहायता चाही। गांधीजी ने जवाब दिया कि तुम दोनों आश्रम में आ जाओ। अशिक्षित होने पर भी तुम आटा पीस सकती हो। किंतु भजन के नाम पर भी दान देने या लेने का कोई औचित्य नहीं। जो भजन व्यक्तिगत स्वार्थ, मुक्ति, सिद्धि आदि जैसे लाभों के लिए किया जाता है , उसमें परमार्थ नहीं होता।

विश्व व्यापार संगठन

बहुपक्षीय व्यापार में नई जान फूंकने के तरीके भी ढूंढे जाएंगे। डब्ल्यूटीओ में भूख एवं खाद्य सुरक्षा के मसले पर अमेरिका और विकसित देशों के नकारात्मक रवैये के विरोध में न्यायोचित मांग के लिए अगुवाई करते हुए भारत के द्वारा आयोजित की जा रही लघु मंत्रिस्तरीय बैठक की ओर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। गौरतलब है कि डब्ल्यूटीओ के ब्यूनस आयर्स सम्मेलन में भारत ने स्पष्ट कहा कि देश की गरीब आबादी को पर्याप्त अनाज मुहैया कराने से जुड़े खाद्य सुरक्षा कानून से वह कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की ओर से यह भी कहा गया कि खाद्य पदार्थों के सार्वजनिक भंडारण का स्थायी हल निकाला जाना चाहिए।

सतीश पेडणोकर

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि पिछले दिनों ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर वार्ता असफल हो गई है। अतएव भारत ने खाद्य सुरक्षा और कृषि संबंधी अन्य मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ के अमीर और विकासशील देशों की छठी मंत्रिस्तरीय बैठक फरवरी 2018 में बुलाई है। जिसमें डब्ल्यूटीओ के 40 सदस्य देशों के भाग लेने की उम्मीद है। इस बैठक में डब्ल्यूटीओ के तहत बहुपक्षीय व्यापार में नई जान फूंकने के तरीके भी ढूंढे जाएंगे। डब्ल्यूटीओ में भूख एवं खाद्य सुरक्षा के मसले पर अमेरिका और विकसित देशों के नकारात्मक रवैये के विरोध में न्यायोचित मांग के लिए अगुवाई करते हुए भारत के द्वारा आयोजित की जा रही लघु मंत्रिस्तरीय बैठक की ओर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। गौरतलब है कि डब्ल्यूटीओ के ब्यूनस आयर्स सम्मेलन में भारत ने स्पष्ट कहा कि देश की गरीब आबादी को पर्याप्त अनाज मुहैया कराने से जुड़े खाद्य सुरक्षा कानून से वह कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की ओर से यह भी कहा गया कि खाद्य पदार्थों के सार्वजनिक भंडारण का स्थायी हल निकाला जाना चाहिए। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि इस सम्मेलन में विकासशील देशों के समूह जी-33 के 47 देशों ने कृषि मुद्दे पर भारत को पूरा समर्थन दिया। साथ ही खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर भारत और चीन में भी एकता देखी गई। लेकिन इस सम्मेलन में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की नकारात्मक भूमिका रही।

भारत के द्वारा उठाई गई खाद्य सुरक्षा की मांग को लेकर इन देशों ने एक साझा स्तर पर पहुंचने से न केवल मना कर दिया वरन ये देश खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने की अपनी प्रतिबद्धता से भी पीछे हट गए। उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूटीओ दुनिया को नियंतग्र गांव बनाने का सपना लिये हुए एक ऐसा नियंतग्र संगठन है, जो दुनिया में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य को सहज एवं सुगम बनाने का उद्देश्य रखता है। 1 जनवरी, 1995 से प्रभावी हुआ डब्ल्यूटीओ केवल व्यापार एवं बाजारों में पहुंच के लिए प्रशुल्क संबंधी कटौतियां तक सीमित नहीं है, यह नियंतग्र व्यापारिक नियमों को अधिक कारगर बनाने के प्रयास के साथ-साथ सेवाओं एवं कृषि में व्यापार पर बातचीत को व्यापक बनाने का लक्ष्य भी संजोए हुए है। लेकिन न केवल ब्यूनस आयर्स में वरन् डब्ल्यूटीओ के गठन के बाद पिछले 22 वर्षो में यह पाया गया है कि डब्ल्यूटीओ के तहत अमेरिका और अन्य विकसित देशों की स्वार्थपूर्ण गुटबंदी ने कृषि एवं औद्योगिक टैरिफ कटौती सहित कई मुद्दों पर विकासशील देशों के हितों को ध्यान में नहीं रखा है। इस संगठन से दुनिया के विकासशील देशों को कई सार्थक लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत जैसे विकासशील देशों को सेवाओं एवं कृषि उत्पादों सहित अनेक सामानों के निर्यात में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। ख्यात अर्थशास्त्री एवं नोबल पुरस्कार विजेता जसेफ ई स्टिग्लिट्ज का कहना है कि डब्ल्यूटीओ का एजेंडा एवं उसके परिणाम दोनों ही विकासशील देशों के खिलाफ हैं। यह पाया गया है कि अमेरिका और विकसित देश आर्थिक संरक्षणवाद की अधिक ऊंची दीवारें खड़ी करते जा रहे हैं। आऊट सोर्सिंग जैसे संरक्षणवादी कदम के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विकसित देशों में घरेलू स्तर पर नौकरियों को बढ़ावा देने की अंतमरुखी नीति का परिदृश्य भारत सहित विकासशील देशों के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन गया है। वस्तुत: विकसित देशों के वीजा रोक और कई वस्तुओं के आयात नियंतग्र संबंधी प्रतिबंध डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य के प्रतिकूल हैं। यही कारण है कि विकासशील देशों के करोड़ों लोग जोर-शोर से यह कह रहे हैं कि जब डब्ल्यूटीओ के तहत पूंजी का प्रवाह पूरी दुनिया में खुला रखा गया है, तो सेवा एवं श्रम के मुक्त प्रवाह और गरीब की खाद्य सुरक्षा पर विकसित देशों के द्वारा तरह-तरह के प्रतिबंध अनुचित और अन्यायपूर्ण हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों ने सब्सिडी, सीमा शुल्क में कटौती, व्यापार की अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए 2001 में दोहा दौर की व्यापार वार्ता शुरू की थी, जिसे वर्ष 2004 में समाप्त होना था। परंतु यह वार्ता विकसित एवं विकासशील देश के आर्थिक हितों की टकराहट के कारण अब तक पूरी नहीं हुई है। मंत्रिस्तरीय वार्ताओं की असफलता की वजह यह है कि अमेरिका सहित कई विकसित देश अपने किसानों को भारी सब्सिडी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन वे अपेक्षा कर रहे हैं कि विकासशील देश किसानों की सब्सिडी कम करें और गरीबों की खाद्य सुरक्षा को भी कम करें। ब्यूनस आयर्स में पिछले दिनों सम्पन्न डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की असफलता की वजह भी यही है। लेकिन डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की कृषि मुद्दों पर बार-बार असफलताके बाद भी हमें यह मानना ही होगा कि अभी भी दुनिया के तमाम देशों के लिए आपसी व्यापार का एक साझा ताना-बाना होना जरूरी है। डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों की संख्या तेजी से बढ़कर 164 हो जाना इस बात का सबूत है कि डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था नियंतग्र व्यापार की सरलता और नियंतग्र व्यापार बढ़ाने के लिए अब भी महत्त्वपूर्ण है। इसके अभाव में उलझनों और दिक्कतों से भरी हुई द्विपक्षीय विदेश व्यापार समझौते की राह ही बचती है, जिसके चलते दुनिया अलग-अलग व्यापार समूह में बंट सकती है। चूंकि डब्ल्यूटीओ के ब्यूनस आयर्स सम्मेलन में भारत द्वारा उठाई गए खाद्य सुरक्षा और खाद्य पदार्थ के सार्वजनिक भंडार के न्यायोचित मुद्दे को ध्यान में नहीं रखा गया। ऐसे में भारत के द्वारा खाद्य सुरक्षा से जुड़े विकासशील देशों की आवाज को डब्ल्यूटीओ के तहत आगे बढ़ाने के लिए फरवरी 2018 में आयोजित की जाने वाली लघु स्तरीय बैठक सार्थक सिद्ध हो सकती है। आशा की जानी चाहिए कि भारत के द्वारा अभूतपूर्व रूप से खाद्य सुरक्षा पर आयोजित की जाने वाली डब्ल्यूटीओ देशों की लघुस्तरीय इस बैठक की न्यायोचित आवाज डब्ल्यूटीओ के आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में विकसित देशों को लचीला रवैया अपनाने के लिए बाध्य करेगी।

चलते चलते

नया साल

वह बेघरों की तरह भी सड़क पर नहीं था। वह भिखमंगों की तरह भी सड़क पर नहीं था। वह कोई गऊमाता नहीं थी कि जिसे दुहने के बाद सड़क पर छोड़ दिया गया हो। वह न रिज से खाने की तलाश में निकला बंदर था।

साल सड़क पर था। जी नहीं, बेरोजगारों की तरह सड़क पर नहीं था। बेशक बेरोजगारों की तरह ही उसे भी अच्छे दिन का इंतजार था। वह बेघरों की तरह भी सड़क पर नहीं था। वह भिखमंगों की तरह भी सड़क पर नहीं था। वह कोई गऊमाता नहीं थी कि जिसे दुहने के बाद सड़क पर छोड़ दिया गया हो। वह न रिज से खाने की तलाश में निकला बंदर था, न ही गली का वह कुत्ता था, जो शेर बराबर होता है और न जाने कितने लोग जिसके खौफ में जीते हैं। नया साल तो नया था। एकदम कोरा। उम्मीदों से भरा हुआ। उत्साह से लबालब। वह निकला तो मस्ती के लिए ही था, लेकिन फिर जाम में फंस गया। जी नहीं, किसानों, बेरोजगारों, छात्रों, व्यापारियों की कोई रैली नहीं थी, कोई धरना या प्रदर्शन नहीं था, जिससे कि जाम लग गया हो और मीडियावालों ने जिसे जी भर के कोसा हो। कोई धार्मिक जुलूस भी नहीं निकला था। कोई सत्संग भी नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे कि जाम लगने का अंदेशा रहता है। कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा था, कोई मैराथन नहीं हो रही थी कि ट्रैफिक पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी हो। न धुंध थी, न कोहरा था, न स्मॉग था कि जिससे विजिब्लिटी कम हो गई हो और जाम लग गया हो। शादियां भी नहीं थी। दिल्ली जैसे महानगरों में अगर कोई तगड़ा सा साया हो और लोग सड़क पर नृत्यलीन हो जाएं, नागिन डांस होने लगे तो भी जाम का खतरा पैदा हो जाता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। नया साल था, एक दम उत्साह से भरा हुआ। वह तो इंडिया गेट घूमने के लिए निकला था। रात को कनॉट प्लेस में मस्ती की थी और सुबह तफरीह के लिए निकल गया था। पर बेचारा फंस गया। उसे क्या पता था कि अमर जवान ज्योति पर जाकर अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करना उसे इतना महंगा पड़ जाएगा। नये साल के पास गाड़ी थी और वह जाम में फंसी थी। न हॉर्न काम कर रहा था और फ्लाइंग गियर कारों में अभी लगे नहीं है। सो वह सड़क पर खड़ा था, फंसा हुआ, जैसे कि नोटबंदी में फंस गया हो।

वह कोई व्यापार नहीं था कि जीएसटी में फंस गया। वह कोई भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं थी कि गतिरोध काशिकार हो गयी हो। वह तो नया साल था। उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ। इस सबके बावजूद उसके लिए शुभकामना तो बनती है।

फोटोग्राफी...

प्राग की ऐतिहासिक धरोहर हैं वल्तावा नदी पर लगातार बने 17 पुल, कई युद्ध हो चुके हैं यहां पर

यह फोटो प्राग की वल्तावा नदी पर बने उन पुलों का है, जिनका निर्माण 18वीं सदी और उसके पहले किया गया। आज यह जगह सैर करने एवं फोटोग्राफी के लिए भी मशहूर है। अमेरिकी फोटोग्राफर ट्रे रेटक्लिफ ने यह फोटो क्लिक किया है। उन्होंने बताया कि वे केवल एक ही दिन के लिए वहां पहुंचे थे। इसके बावजूद वे इस शहर की फोटोग्राफी का अवसर छोड़ना नहीं चाहते थे। रात में कई जगह जगह सैर करने के बाद उन्हें यह स्पॉट मिला और नदी पर बने लगातार पुलों का दृश्य क्लिक किया। उनके अनुसार प्राग में एक ही नदी पर 17 पुल बने हैं। वर्ष 1620 से लेकर दूसरे विश्वयुद्ध तक कई संघर्ष यहां हो चुके हैं। यहां सबसे पुराना 'चार्ल्स ब्रिज' है, उसे 15वीं सदी की शुरुआत में तैयार किया गया था। उसके पहले वल्तावा नदी पर पहला पुल पत्थर का बना था, वर्ष 1342 की बाढ़ में वह बह गया था। वर्ष 1620 में यहीं 'व्हा इट माउंटेन' की लड़ाई हुई, जो यूरोप के सबसे भयावह 'थर्टी ईयर्स वॉर' (1618-1648) का हिस्सा था। PhotoPin.com

शानदार प्रदर्शन

भारतीय क्रिकेट का नक्शा बदला है। अब क्रिकेट चंद टीमों की बपौती नहीं रह गई है। इसकी वजह राष्ट्रीय चैंपियनशिप के तौर पर खेले जाने वाली रणजी ट्रॉफी में नये-नये चैंपियन सामने आने लगे हैं। इस बार इसका खिताब विदर्भ ने पहली बार जीता है। उसे यह सफलता 266 मैच खेलने के बाद मिली है। पिछली बार यानी 2016-17 के सत्र में गुजरात चैंपियन बनी थी। इससे पहले 2010-11 और 2011-12 में राजस्थान की टीम चैंपियन बनी थी। पर इन टीमों के चैंपियन बनने पर भी आप इनके खिलाड़ियों को टीम इंडिया में खेलते नहीं देख पाते हैं। इस वजह से ही रणजी ट्रॉफी अपनी पुरानी चमक को एकदम से खो बैठी है। अब टीम इंडिया में खेलने वाले खिलाड़ी रणजी मैचों में खेलते कम ही नजर आते हैं। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि रणजी ट्रॉफी में गेंद या बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के नाम पर टीम इंडिया के लिए कम ही विचार किया जाता दिखता है। हमारे सामने गौतम गंभीर का उदाहरण है। वह काफी समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। वह रंगत पाने के लिए रणजी मैचों में खेले और उन्होंने नौ मैचों में 56.91 के औसत से 683 रन बनाए, जिसमें तीन शतक शामिल हैं। पर गंभीर इस सबके बावजूद चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में असफल रहे। इसी तरह इस सीजन में कर्नाटक के मयंक अग्रवाल ने सर्वाधिक 1160 रन बनाए, जिसमें पांच शतक शामिल हैं। पर उनके भी टीम इंडिया में खेलने की कोई संभावना नहीं दिखती है। यही नहीं इस सीजन के टॉप छह रन बनाने वाले-फैज फजल (912 रन), एस रामास्वामी (775 रन), अनमोलप्रीत (753 रन), एच विहारी (752 रन) और गंभीर में से किसी के भी टीम इंडिया में खेलने की संभावना नहीं है। हम अगर यह कहें कि बल्लेबाजों के मुकाबले गेंदबाजों की राह थोड़ी आसान है तो इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है। पेस गेंदबाजों को किसी-न-किसी प्रारूप में खेलने का मौका मिल जाता है। केरल के लिए खेले जलज सक्सेना ने इस बार सर्वाधिक 44 विकेट लिये। पर वह 31 साल के होने से टीम इंडिया में शायद ही खेल पाएं। हां, इतना जरूर है कि इस सीजन में दो हैट्रिक से 39 विकेट लेने वाले आर गुरबानी और दिल्ली के 34 विकेट लेने वाले नवदीप सैनी जरूर टीम में स्थान पा सकते हैं। सच यही है कि यदि इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वालों को टीम इंडिया में जगह मिलने की गुंजाइश रहती तो और भी युवा अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ सकते थे। मुझे याद है कि एक समय था जब कोई दिग्गज खिलाड़ी फॉर्म खो देता था, तो उसे घरेलू क्रिकेट में खेलने को भेज दिया जाता था। पर अब दिग्गज खिलाड़ी इसमें खेलने में परहेज करते हैं। जब कभी उनके सामने खेलने का मौका होता भी है तो वह खेलने के बजाय आराम करना बेहतर समझते हैं। जाफर ने इस सीजन में 54.09 के औसत से 595 रन बनाए। असल में जाफर ने रन बनाने से भी महत्त्वपूर्ण काम कोच चंद्रकांत पंडित के साथ मिलकर साथी खिलाड़ियों की मानसिकता को विजेता टीम के खिलाड़ी के रूप में बदला, जिसका परिणाम सभी के सामने है। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रशांत वैद्य ने बताया कि वह चंद्रकांत पंडित को कोच बनाने के लिए पांच-छह साल से लगे थे पर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। पंडित अब तक मुंबई के अलावा, राजस्थान और गुजरात को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना चुके हैं। पर उनके इस प्रयास का राष्ट्रीय स्तर पर क्या फल मिला है? इसलिए इस चैंपियनशिप की अहमियत बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इसमें चमक बिखेरने वाले खिलाड़ियों को उसका ईनाम पूरी ईमानदारी से दिया जाए। ऐसा करके सीढ़ियां चढ़ रहीं टीमें अपना स्थान सुरक्षित बना सकती हैं।

कैराना मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मी की मौत

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में घायल सिपाही अंकित तोमर की बुधवार देर रात नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में मौत हो गई। प्रदेश सरकार ने शहीद अंकित के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ ने शहीद सिपाही की वीरता और साहस की प्रशंसा करते हुए उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। आर्थिक सहायता के रूप में 40 लाख रुपए शहीद की पत्नी व 10 लाख रुपए उनके माता-पिता को दिए जाएंगे। मंगलवार को बदमाश साबिर से हुई मुठभेड़ में अंकित के सिर व छाती में गोली लग गई थी। दिमाग में गोली धंसने से वह कोमा में चले गए थे। उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था। देश के वरिष्ठ चिकित्सकों ने अंकित के ब्रेन में धंसी गोली निकालने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। साबिर मुठभेड़ में मारा गया था।

चैनलों व मीडिया द्वारा प्रकाशित खबर पर मदरसा बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट की

लखनऊ(ईएमएस)। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने कुछ न्यूज चैनलों व प्रिन्ट मीडिया द्वारा प्रसारित व प्रकाशित खबर कि कई मदरसे,बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे,के सम्बंध में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2017 में कुल 2773 मदरसे,बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।इनमें अध्ययनरत कुल 370436 छात्र व छात्राओं ने परीक्षा दी,जिसमें से 85605 व्यक्तिगत (प्राईवेट) परीक्षार्थी थे।उन्होंने कहा कि इस वर्ष मदरसा पोर्टल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा को सरल एवं सूचारू बनाने का प्रयास किया गया है। पोर्टल पर 3691 आलिया एवं उच्च आलिया स्तर के मदरसों द्वारा अपना विवरण अपलोड किया गया है, जो गत वर्ष के 2773 मदरसों के सापेक्ष लगभग 900 अधिक हैं।इनमें अध्ययनरत 2,68098 छात्र व छात्रायें ऑनलाईन आवेदन कर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले छात्र व छात्राओं के परीक्षा फार्म सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्या द्वारा अग्रसारित किये जा सकते है।श्री गुप्ता ने कहा कि मदरसा बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये किसी भी प्रकार की असुविधा से मदरसों व छात्र एवं छात्राओं द्वारा अवगत नहीं कराया गया है।आवेदन करने की अन्तिम तिथि आगामी 20 जनवरी निर्धारित की गयी है।वर्ष 2018 की परीक्षा आगामी मार्च व अप्रैल में प्रस्तावित है।

डीएम व एसपी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में सुनीं फरियादियों की शिकायतें

गोंडा(ईएमएस)। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डीएम गोण्डा जेबी सिंह व पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार सिंह ने तहसील सदर में जिला स्तरीय सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुचकर फरियादियों की शिकायतें सुनीं और उनके निराकरण के आदेश दिए।डीएम ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए है कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराएं।सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर में पहुंचकर डीएम ने लम्बित शिकायतों का निरीक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि तहसील सदर अन्तर्गत सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त कुल 34 शिकायतें निस्तारण हेतु लम्बित है। जनपद में सम्पूर्ण समाधान में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का प्रतिशत 98 प्रतिशत पाया गया। डीएम ने लम्बित शिकयतों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित कर रिपोर्ट देने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए है।इसके अलावा सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटवाने के निर्देश राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए हैं।सम्पूर्ण समाधान दिवस में बाबादीन पुत्र श्यामलाल निवासी मिश्रौलिया माफी ने जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर अवगत कराया कि गांव के ही दंबग व्यक्ति द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

आवासों के निर्माण कार्य इस माह जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिये

लखनऊ(ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)एवं राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा महेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत निर्माणाधीन 08.85 लाख आवासों को इस माह जनवरी के अन्त तक पूरा कर लिया जाये।ग्राम्य विकास मंत्री यहां योजना भवन में प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों तथा संयुक्त विकास आयुक्तों की एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे,उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा और लापरवाह तथा उदासीन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही भी की जायेगी।उन्होंने कहा कि विभाग में किसी स्तर पर भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जायेगा।आवासों के स्वीकृति में जिस जनपद से शिकायतें प्राप्त हुई, उसमें लिप्त ग्राम प्रधान तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करके कड़ी कार्यवाही की गयी। डा महेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाई जा रही हैं, जिसके डर से जिन अपात्रों को मकान मिल गये थे वह वापस कर रहे हैं।इसके बाद भी जांच के उपरान्त जो फर्जी पाये जायेंगे,उनसे आवास की धनराशि की वसूली तथा मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्यवाही की जायेगी।उन्होंने कहा कि जनपद गोण्डा में 1800 अपात्र लाभार्थियों ने आवास वापस किया है। ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड तथा उसके आस-पास के जनपदों में हर साल पेयजल की समस्या विकराल रूप ले लेती है।

आईटी सेक्टर को 5 साल तक स्टेट जीएसटी से छूट,दो दिवसीय आईटी-आईटीईएस निवेशक सम्मेलन में की घोषणा

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर हमारी उच्च प्राथमिकता में है। इस क्षेत्र की नई इकाइयों को उत्पादन शुरू करने की तिथि से अगले 5 वर्ष तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (स्टेट जीएसटी) में 100% छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहां दो दिवसीय आईटी आईटीईएस निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आईटी क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए औद्योगिक नीति में इस क्षेत्र की रियायतों के लिए और संशोधन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बिहार आईटी आईटीईएस इनवेस्टमेंट प्रमोशन विजन 2017 और बिहार ईएसडीएम विजन 2017 को जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में बनी नई औद्योगिक नीति में 10 क्षेत्रों को प्राथमिक सूची में रखा गया।

कॉन्क्लेव की खास बातें

आईटी क्षेत्र में कम से कम 5 करोड़ के निवेश व 50 से अधिक नौकरी देने वाली यूनिट को विशेष छूट। आईटी यूनिटों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ होगी।

आईटी सेक्टर में नियोजित सामान्य कर्मियों को 50% तथा एससी/एसटी एवं महिलाकर्मियों को 100% ईएसआई और ईपीएफ राशि पर 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। लाभ उन्हें मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी होंगे।

पटना में खुलेगा राष्ट्रीय साइबर सिक्यूरिटी ट्रेनिंग सेंटर: रविशंकर

केंद्रीय सूचना-प्रावैधिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में साइबर सिक्यूरिटी से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की। यह संस्थान डिजिटल पुलिसिंग, साइबर सिक्यूरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण देगा। इसके लिए आईआईटी या एनआईटी पटना को नॉलेज पार्टनर बनाया जाएगा। संस्थान की स्थापना सीडैक करेगी।

शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही

हरदोई(ईएमएस)। विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि आईजीआरएस के अन्तर्गत किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाये और सभी शिकायतों का निस्तारण समयसीमा के अन्दर किया जाये।उन्होने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी और शिकायतों के निस्तारण में देरी करने वाले विभागीय अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों का संबन्ध बैंकों से है वह सभी अधिकारी डीएलआरसी की बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे ताकि बैठक में बैंक संबन्धी समस्याओं का निस्तारण कराया जा सके।स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी डा पीएन चतुर्वेदी को निर्देश दिये कि वह अपने साथ-साथ अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व डिप्टी सीएमओ प्रति माह नियमित सीएचसी व पीएचसी का निरीक्षण करें तथा 15 जनवरी तक सभी सीएचसी व पीएचसी पर बायोमैट्रिक मशीन लगवाना सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने कहा कि 16 जनवरी से सभी सीएचसी व पीएचसी पर बायोमैट्रिक उपि-स्थति दर्ज की जायेगी जिसकी मानीटरिंग सीधे उनके कम्प्यूटर पर की जायेगी।दवाओं की सप्लाई की देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जिन एजेन्सियों द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर दवाओं की आपूर्ति नही की जा रही है उनके विरूद्ध कार्यवाही करें और सभी सीएचसी व पीएचसी पर दवाओं आदि की उपलब्धता बनाई रखी जाये ताकि किसी भी मरीज को बाहर से दवाई लेनी न पड़े।बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि सभी एमओआईसी अपने क्षेत्र के पांच उपकेन्द्रों को चुनकर उनमें समस्त व्यवस्थायें कराना सुनिश्चित करें तथा लाभार्थियों को भुगतान समय पर किया जाये।उन्होने कहा कि पिछले 06 माह से अब तक जिन लाभार्थियों का भुगतान शेष रह गया है उनकी सूची उपलब्ध करायें।मनरेगा की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा को निर्देश दिये कि मनरेगा का भुगतान शतप्रतिशत कराया जाये तथा मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जाये।उन्होने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने कार्यालयों में लैण्डलाइन फोन लगवायें।जिलाधिकारी ने कहा कि खण्ड विकास अधिकारियों की उपस्थिति की जानकारी उनके लैण्डलाइन नम्बर पर फोन करके ली जायेगी। पीडब्ल्यूडी,पीएमजीएसवाई व अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि सभी कार्यदायी संस्थायें अपने-अपने कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर गुणवत्तापरक करायें।आगंनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के संबन्ध मे जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था आरईएस के अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन के निर्देशानुसार 26 जनवरी से पहले सभी आगनबाड़ी केन्द्रो का निर्माण पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।नममि गंगे के तहत गंगा किनारे के 11 गांवों को ओडीएफ करने के संबन्ध में जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिये कि जनपद के सभी गांवों में तैनात समस्त सफाई कर्मचारियों की लिस्ट नाम और नम्बर सहित प्रेषित करें।उन्होने कहा कि जिन सेक्रेट्रीयिओं का स्थानान्तरण अन्य विकास खण्ड में हो गया है और अभी तक उन लोगों ने चार्ज नही दिया है तो उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायें। उन्होने कहा कि सभी सेक्रेटरी से ग्राम पंचायतवार मास्टर रजिस्टर बनवाये जाये जिसमें सभी विभागों की योजनायें के कार्य अंकित हों।जिलाधिकारी ने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि सप्ताह में तीन निरीक्षण करें और निरीक्षण आख्या कलेक्ट्रेट में स्थापित निरीक्षण सेल में फोटो सहित उपलब्ध करायेंगे।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 को सफल बनाने के लिए नगर निकायों से आग्रह किया

लखनऊ(ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नगर निकायों के महापौर, अध्यक्षों व पार्षदों तथा सभासदों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ''स्वच्छ सर्वेक्षण-2018'' के तहत अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का आग्रह किया है।उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आपके प्रयासों से उप्र के शहरों की स्वच्छता सुनिश्चित होगी तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में प्रदेश के शहर एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकेंगे।नगर विकास मंत्री ने कहा कि यह सर्वेक्षण वर्ष 2017 में 434 शहरों में किया गया था,जबकि इस वर्ष 4041 शहरों के बीच किया जा रहा है।पिछले वर्ष इस सर्वेक्षण में सम्मिलित प्रदेश के 60 शहरों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी।इस वर्ष नगर विकास विभाग द्वारा समय-समय पर संबंधित अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण संबंधी गोष्ठियां कर सुझाव दिए गये हैं।स्वच्छ सर्वेक्षण में 4000 अंक हैं जिसमें से 1400 अंक सिटीजन फीडबैक के हैं जिसमें नागरिकों से प्रतिक्रिया के तहत यह पूछा जाता है कि आपको स्वच्छता रैंकिंग के लिए आपका शहर सर्वेक्षण -2018 में भाग ले रहा है,इसके बारे में जानकारी है अथवा नहीं।नागरिक प्रतिक्रिया के अन्तर्गत हर प्रश्न के लिए अंक निर्धारित किये गये हैं,जिसका कुल योग 1400 है।इसके तहत नागरिकों से यह भी प्रतिक्रिया ली गयी कि पिछले साल के मुकाबले आपका क्षेत्र साफ है अथवा नहीं,इस साल क्या आपने सार्वजनिक क्षेत्र में कूड़े के डिब्बों का उपयोग शुरू कर दिया है?क्या आप इस वर्ष अपने घर से अलग-अलग कचरा एकत्र किये जाने की व्यवस्था से संतुष्ट हैं?इस तरह अन्य बिन्दुओं पर जनता से प्रतिक्रिया ली गयी।श्री खन्ना ने आग्रह किया कि सभी नगर निकाय स्वच्छता के तहत सभी मुद्दों पर अच्छा कार्य करते हुए नागरिकों को एक सकारात्मक संदेश दें और उनकी सहभागिता प्राप्त कर सिटीजन फीडबैक मद हेतु आरक्षित अंकों में प्रदेश के शहरों को अच्छे अंक प्राप्त कराये। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।इसके अलावा नगर विकास विभाग पूर्ण रूप से सजग एवं प्रयासरत है कि वर्ष 2018 में उप्र के शहर अपने-अपने क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 के सभी मापदण्डों पर अच्छा प्रदर्शन कर खरा उतरें।

योगी सरकार ने मदरसों में अवकाश की संख्या घटाई

मदरसों ने विरोध करते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार की मांग की

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए नए साल में छुट्टियों की संख्या घटा दी है। मदरसों ने इसका विरोध करते हुए सरकार से इस पर फिर से विचार करने की मांग की है, वहीं सरकार ने इसे छात्र हित में उठाया गया कदम बताया है। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता की ओर से जारी कैलेंडर में दीपावली, दशहरा, महानवमी, महावीर जयंती, बुद्धपूर्णिमा, रक्षाबंधन और क्रिसमस की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, वहीं, रमजान के दिनों में दी जाने वाली 46 दिन की छुट्टियों की संख्या घटाकर 42 कर दी गई है। इसके अलावा मदरसों के प्रबंधकों के विवेकाधीन 10 छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है. सरकार ने पिछले साल के मुकाबले मदरसों में छुट्टियों के अवसर 17 से बढ़ाकर 25 कर दिए हैं, लेकिन 10 दिन की विवेकाधीन छुट्टियां घटा दी हैं। पिछले साल जहां मदरसों में कुल 92 छुट्टियों की व्यवस्था थी, वहीं इस साल इनकी संख्या 86 ही रहेगी। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मदरसों में छुट्टियां घटाये जाने के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि सभी शिक्षण संस्थाओं के छात्र अपने महापुरुषों के बारे में जानें, इसलिये सभी शिक्षा परिषदों और विश्वविद्यालयों में महान विभूतियों की जयंती अथवा पुण्यतिथि पर दी जाने वाली छुट्टियां रद्द की गई हैं। इसके अलावा मदरसों के प्रबंधकों के विवेकाधीन 10 छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है. सरकार ने पिछले साल के मुकाबले मदरसों में छुट्टियों के अवसर 17 से बढ़ाकर 25 कर दिए हैं, लेकिन 10 दिन की विवेकाधीन छुट्टियां घटा दी हैं। इस बीच टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर छुट्टियों में कटौती पर पुनर्विचार की मांग की है।

निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारी समुचित एवं सम्पूर्ण निस्तारण करें

अमरोहा(ईएमएस)। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकास खण्ड धनौरा परिसर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों को गम्भीरता से सुना और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारी समुचित एवं सम्पूर्ण निस्तारण करेगें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसामान्य को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को सुगमता से उपलब्ध कराया जायेगा।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सामान्य जन द्वारा सुविधाओं एवं समय के अपव्यय को समाप्त करना है।किसी भी शिकायत को लम्बित न रखा जाए और 07 दिन के अन्दर शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाये।उन्होने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से अधिक नही होना चाहिए।उन्होने कहा कि जनपद स्तरीय अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप पूर्ण मेहनत,ईमानदारी और मनोयोग से कार्य करें।शासन की मंशा है कि जो योजनाऐं चलाई जा रही है उनका लाभ सिर्फ लाभार्थी को मिलना चाहिए।उन्होने कहा कि गरीबों का हक किसी भी कीमत पर छीना नही जाये और गरीबों, महिलाओं और किसानों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें।और उनकी समस्याओं का निस्तारण ईमानदारी पूर्वक करें।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शिकायतों का शीघ्रता से समाधान गुणवत्ता पूर्ण वास्तविकता से करना सुनिश्चित करें।उन्होने कहा कि शिकायत के निस्तारण में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है तो सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश देकर कहा कि जो शिकायतें सम्पूर्ण समाधान दिवस में आई हैं उन शिकायतों की जांच की जाये और आने वाली शिकायतों का निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र किया जाये।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से होगा निस्तारण

मैनपुरी(ईएमएस)। विषम परिस्थितियों में पूरे जज्बे के साथ देश की सरहदों की रक्षा करने वाले सैनिकों के कारण ही देशवासी सुरक्षति जीवन यापन कर रहे है।सेना से सेवानिवृत्त होकर आने वाले सैनिकों का सभी को सम्मान करना चाहिए उनकी समस्याओं का सवीच्च प्राथमिकता पर सभी विभागों में समाधान हो,उन्हें मिलने वाली सुविधाएं समय से मिले इसके माकूल इंतजाम कराए जाएं।सैनिकों के साथ किसी भी कार्यालय,बैंक में अभद्र व्यवहार किया गया तो दोषी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी प्रदीप कुमार ने सैनिक बंधु की बैठक में सैनिकों की समस्याएं सुनने के उपरांत सैनिकों को आश्वस्त किया कि उनकी प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता पर निदान होगा,उनके द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे उन्हें ऑनलाइन कर निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने सैनिक कल्याण अधिकारी से कहा कि सैनिकों द्वारा जो भी शिकायती आवेदन पत्र दिए जाएं उन्हें कलेक्ट्रेट के शिकायत पटल पर उपलब्ध कराया जाए,जहां से उनकी शिकायतों को ऑनलाइन कराया जाएगा।उन्होंने सैनिकों से उनकी समस्याओं की जानकारी करने पर कई सैनिकों ने बताया कि उन्हें जो पट्टे मिले थे,उन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है।इस पर उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक गांव में पट्टों,सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों का चिन्हांकन कराया जा रहा है।जिन्हें अभियान चलाकर हटाया जाएगा जो पात्र होगा,भूमि पर उसी का कब्जा रहेगा।अनाधिकृत कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।कई शहीद सैनिकों की विधवाओं ने राशन कार्ड बनवाने की मांग की जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि शासनादेश के अनुसार जैसे ही राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी सबसे पहले सैनिकों के परिवारों के राशन कार्ड बनवाये जाएंगे।श्री कुमार ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विरासत के शस्त्र लाइसेन्स हस्तान्तरण करने की मांग पर कहा कि आर्म?स एक्ट में लाइसेंस धारक के जीवित रहने पर उत्तराधिकारी को शस्त्र लाइसेंस हस्तांतरण करने का प्रावधान नहीं है,यदि कोई दिशा निर्देश मिले तो प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों से की जा रही बदसलूकी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही होगी,भारतीय स्टेट बैंक शाखा बेवर के जिस कर्मी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है।

मरीजो के स्वास्थ्य पर लापरवाही छमय नही डीएम

मऊ ईएमएस। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिलाधिकारी प्रकाश विन्दु की अध्यक्षता में कलेक्टेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय सहित सभी समुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों डाक्टर समय से बैठें और ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायें इसमें किसी भी प्रकार लापरवाही क्षम्य नही होगी। जिलाधिकारी द्वारा जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को भुगतान कम होने पर नराजगी व्यक्त की गयी तथा अगली बैठक में यह कमी दूर करने के निर्देश दिये एवं भुगतान शत प्रतिशत होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए ब्लाक स्तर पर इसके जिस्मेदारी निर्धारित करने के निर्देश दिये। जननी सुरक्षा में कम भूगतान होने पर सभी लाभार्थियों का जॉच करने के लिए उपजिलाधिकारी को जॉच करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षति मातृत्व अभियान जिसके तहत प्रत्येक माह को नौ तारीख को गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को जॉच करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग में हो रहे निर्माण कार्यो की समीक्षा की गयी। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा टीकाकरण के खराब प्रगति नराजगी व्यक्त की गयी और इसकी प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये तथा जिस समुदायिक क्षेत्र में टीकाकरण कम है उस ब्लाक चिकित्सा अधीक्षक को कारण बताओ नोटीस जारी करने के निर्देश दिये गये।

उक्त अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी पुरूष, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महिला, स्वास्थ्य शिक्षाधिकारी सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहें।

बालू कारोबार से जुड़े युवक की मौत, एसडीएम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

बांदा (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गोरेपुरवा गांव के बालू कारोबार से जुड़े एक युवक की मौत के मामले में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और उनके दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुक्दमा दर्ज किया है। अपर पुलिस अधीक्षक लाल भरत कुमार पाल ने बताया कि नरैनी में खनिज जांच चौकी के पास जब्बर के खेत में बालू कारोबार से जुड़े गोरेपुरवा निवासी युवक अफसार (45) का शव पुलिस को मिला था। मृतक के परिजनों ने उपजिलाधिकारी नरैनी और उनके सुरक्षाकर्मियों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मंगलवार देर शाम नरैनी कोतवाली में मृतक की पत्नी शहरुन निशां की तहरीर पर एसडीएम और उनके सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा-302 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जनता के हितों के लिए योजनायें क्रियान्वित करें

गोरखपुर(ईएमएस)। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता के हितों के लिए योजनायें क्रियान्वित करें।आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि पम्प कैनाल से पानी नहर के द्वारा खेतों तक पहुचाना था परन्तु इसे समय से नही पहुचाया गया।विभागीय अधिकारी भविष्य में आवश्यकता का आंकलन करके तद्नुसार योजना क्रियान्वित करें।उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की ब्याज दर सबसे कम 4 प्रतिशत होता है।इससे अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करें।उन्होंने निर्देश दिया कि मार्च तक जिले के सभी किसानो का फार्म भरवाकर एकत्र करें तथा जून माह तक सभी का किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दें।इससे किसानों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वृद्धावस्था,विधवा एंव दिव्यांग सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ देने का सरकार ने निर्णय लिया है।पहले इन तीनों का जिलेवार लक्ष्य होता था। उन्होंने तीनों विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी पात्र व्यक्तियों का फार्म भरवायें तथा उन्हें योजना का लाभ दिलायें।इसके लिए विशेष कैम्प आयोजित किये जायें।बाल स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग तथा बेसिक शिक्षा विभाग सुनिश्चित करे कि सभी छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो जाये तथा सभी का स्वास्थ्य कार्ड जारी हो जाये।स्वास्थ्य कार्ड में दर्शायी गयी कमियों के अनुसार उनको समुचित इलाज भी मिले। अपर मुख्य सचिव ने पिछली बैठक में ही सीएचसी व पीएसी पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने वाली दवाओं की सूची मांगी थी परन्तु इसे उपलब्ध न कराने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया।आज भी स्वास्थ्य विभाग उन्हें सूची उपलब्ध नही कराया जा सका,इस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया तथा दो दिन में सूची डीएम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।नगरनिगम क्षेत्र में लगाई जाने वाली 31500 एलईडी लाइट के बारे में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि 9900 लाइट लगाई जा चुकी है, शेष मार्च तक लगा दी जायेगी।अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता की योजनाओं,निर्माण कार्यों की समीक्षा भी किया।उन्होंने अधिकारियों से शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों की जानकारी लिया।जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वस्त किया कि उनके निर्देशानुसार विकास कार्यों का संचालन किया जायेगा।

क्रांति समय

महाराष्ट्र कोरेगांव का असर सूरत में भी

दलित संगठनों ने रिंग रोड आंबेडकर प्रतिमा से कलेक्ट्रालय तक निकाली रैली

प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय के बाहर रोड पर ही सो गए

सूरत। महाराष्ट्र के पुणे में भीमा कोरेगांव युद्ध के 200वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर हुए सम्मेलन में हिंसा की आग की ज्वाला सूरत तक भी पहुंच गई। मुम्बई, औरंगाबाद, अहमदनगर सहित कई शहरों के बाद सूरत के दलित संगठनों ने भी मानदरवाजा रिंग रोड स्थित डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा से कलेक्टर कार्यालय तक रैली का आयोजन किए। जहां कलेक्टर को आवेदन पत्र देने के लिए गए और कार्यालय के बाहर रोड पर ही प्रदर्शनकारी सो गए। जिससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई थी।

महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार को भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर हुए सम्मेलन के दौरान हुई हिंसा में एक युवक की मौत हो गई थी। जिसके कारण दलित संगठनों ने मंगलवार से महाराष्ट्र के शहरों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दलित संगठनों ने सूरत उधना रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर तथा एक मालगड़ी को रोक दिए। इसके बाद गुरुवार को दलित संगठनों ने फिर से रिंग रोड डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाले। कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचने के बाद प्रदर्शन करने वाले कार्यालय के बाहर सार्वजनिक रास्ते पर ही लेट गए। जिसके कारण कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ा।

महाराष्ट्र में हुई हिंसा का असर सूरत के कपड़ा बाजार पर भी दिखा

करीब 200 करोड़ का टेक्सटाइल गुड्स जहां के तहां जाम

सूरत। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई व्यापक हिंसा का असर सूरत कपड़ा मार्केट से होने वाली डिलीवरी पर भी पड़ा है। करोड़ों रुपए की टेक्सटाइल सामग्री जो बाह गांव जाती थी उसे जहां के तहां रोक देने की स्थिति पैदा हो गई। जिसके कारण करीब 200 करोड़ के टेक्सटाइल मैटेरियल से भरे वाहनों को भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रोक दिया गया।

सूरत टेक्सटाइल ट्रांसपोर्टस वेलफेयर एसोससिएशन के प्रमुख युवराज देसले के बताए अनुसार महाराष्ट्र में फैली हिंसा के कारण अधिकांश ट्रक-टेम्पो नागपुर स्टेट हाइवे के पास रोक दिए गए हैं। सूरत से अहमदाबाद, मुम्बई और कोलकता के इन तीन रूटों पर प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट में टेक्सटाइल गुड्स जाता है। मुम्बई कोलकाता रूट पर रोज 300 ट्रकों में कपड़ो की डिलीवरी होती है। मंगलवार को देर शाम से ही इन तीनों रूटों पर जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि एक ट्रक में करीब 60 से 80 लाख का माल डिलीवरी होता है। इस तरह देखा जाए तो 180 से 200 करोड़ के गुड्स की डिलीवरी रोक दी गई थी। अब स्थिति सामान्य होती लग रही है। जिससे टेक्सटाइल्स सामग्री से भरे वाहनों को रवाना करने की तैयारी भी की जा रही है।

पांडेसरा के युवक ने फांसी पर झूल दी जान

सूरत। पांडेसरा के विनायक नगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने किसी कारणों से अपने घर में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली।

घटना के बारे में नई सिविल अस्पताल और पांडेसरा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पांडेसरा के विनायक नगर, बमरोली रोड पर रहने वाले नंदूभाई दौलतभाई झंझाकर (45 वर्ष) ने किसी अज्ञात कारणों से अपने घर में फांसी पर झूल गए। नंदूभाई को बेहोशी की हालत में उनके बेटे किरणभाई सिविल अस्पताल में ले गए जहां पर चिकित्सकों ने मृत घषित कर दिया। पांडेसरा पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

अपहरण की गई बच्ची का शव पेड़ से लटका मिला

एक दिन पहले बच्ची का किसी ने किया था अपहरण

बारडोली। चलथाण गांव में शाम के समय घर के सामने खेल रही छह साल की बच्ची का किसी ने बहका-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। इसके बाद गत रोज सुबह ही वांकानेडा गांव के एक खेत में स्थित पेड़ के साथ फांसी लगी हालत में लाश मिलने से सनसनी मच गई है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू की है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पैनल पीएम कराने के लिए बच्ची की लाश को सूरत लाया गया। चलथाण में रहने वाले मूलत: मध्यप्रदेश का परिवार धंधा-मजूरी करके गुजर करता है। इस परिवार की छह वर्ष की मासूम बच्ची शाम के समय घर के पास ही खेल रही थी। उसी समय कोई व्यक्ति अपने नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए बच्ची को बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया। काफी समय बीतने पर जब बच्ची घर नहीं आई तो परिजन उसे खोजने लगे। जब उसका कहीं पता नहीं चला तो कडोदरा पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराने पर पुलिस मामले की जांच शुरू की थी। इसी दौरान गत रोज सुबह ही बच्ची को वांकानेडा गांव के एक खेत में स्थित पेड़ के साथ पायजामा से फांसी देकर हत्यारा फरार हो गया था। जानकारी पाने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है कि नहीं? इसकी जांच के लिए लाश को पैनल पीएम के लिए सूरत भेजा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है या कि मात्र हत्या ही की गई है।

एक-दो दिन में हो सकता है विपक्ष के नेता का ऐलान

अहमदाबाद (ईएमएस)। कांग्रेस अगले एक-दो दिन में विपक्ष के नेता के नाम का ऐलान कर सकती है। अहमदाबाद में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन में केन्द्रीय निरीक्षकों की मौजूदगी में विधायकों की बैठक के बाद अब विपक्ष का नेता तय करने की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमांड को सौंप दी गई है। कांग्रेस के सभी विधायकों और प्रदेश नेताओं के साथ एआईसीसी के महासचिव और गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्रसिंह ने व्यापक चर्चा के बाद प्रत्येक विधायक से व्यक्तिगत बातचीत की। विपक्ष के नेता के संदर्भ में शक्तिसिंह गोहिल, अर्जुन मोढवाडिया और सिद्धार्थ पटेल का अभिप्राय भी लिया गया है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑर्ट सिल्क विविंग इंडस्ट्री की 6 को वार्षिक सामान्य सभा

बजट से पूर्व सरकार के समक्ष रखेंगे मांग

सूरत। टेक्सटाइल के विविध सेक्टर के लिए केन्द्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय की मशीनरी अपग्रेडशन फंड की विविध योजनाओं के उद्यमियों से अर्जी मंगाई जा रही है, परंतु उद्यमियों को इसके फंड को लेने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। 6 जनवरी को द सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के बोर्ड रूम में फेडरेशन आफ इंडियन ऑर्ट सिल्क विविंग इंडस्ट्री (फीयास्वी) की 40वीं वार्षिक सामान्य सभा होगी।

फीयास्वी के चेयरमैन भरत गांधी ने इस बारे में बताया कि टफ फंड के अभाव से उद्यमियों की टफ की अर्जियां पेंडिंग में हैं। फीयास्वी के पूर्व चेयरमैन अरुण जरीवाला ने कहा कि पहले सरकार से 7 वर्ष के डेप्रीएशन स्कीम को अमल के लिए भी मांग की गई थी। वणकर संघ के प्रमुख रजनीकांत बचकानीवाला के बताए अनुसार टफ की स्कीम में हाल के स्तर पर स्पीनिंग क्षेत्र में मिलने वाले लाभ को खत्म कर दिए हैं। विविंग और प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए नई अर्जी स्वीकार की गई, लेकिन फंड रिलीज नहीं किया जाता। अतएव फीयास्वी की सामान्य सभा में विविंग संस्थाओं के प्रतिनिधि महाराष्ट्र सेलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, मुम्बई से हाजिर रहेंगे। जिनके समक्ष जीएसटी से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करके बजट से पूर्व ही सरकार के समक्ष मांग रखी जाएगी।

परेश धानाणी को विपक्ष का नेता नहीं बनाने पर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन : हार्दिक

सूरत (ईएमएस)। पास नेता हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस को धमकी दी है कि यदि अमरेली के युवा विधायक परेश धानाणी को विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया तो वह कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में राज्यभर में भाजपा को हराने की अपील करने वाले पास नेता हार्दिक पटेल ने अब कांग्रेस को धमकी दी है। सूरत में हार्दिक पटेल ने कहा कि यदि कांग्रेस परेश धानाणी को गुजरात विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनाती है तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ देंगे। हार्दिक पटेल ने परेश धानाणी के लिए आंदोलन छेड़ने की धमकी देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हार्दिक पटेल राजद्रोह के मामले में हाजिरी लगाने सूरत आए थे। गौरतलब है गुजरात चुनाव के दौरान हार्दिक पटेल ने एक जनसभा में कहा था कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो परेश धानाणी राज्य के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन अब तो कांग्रेस के लिए विपक्ष का पद महत्वपूर्ण है। अब तक माना जा रहा था कि परेश धानाणी को ही विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। लेकिन इस पद की दौड़ में कुंवरजी बावलिया के शामिल होने से मामला पेचीदा हो गया है। बावलिया का दावा है कि सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। इसके अलावा वे लगातार पांच दफा चुनाव जीते हैं और सांसद भी रह चुके हैं। बावलिया के अलावा आहिर समाज के नेता और विधायक विक्रम माडम के भी विपक्ष के नेता पद के लिए दावेदारी ने कांग्रेस की दुविधा बढ़ा दी है। विपक्ष के नेता पद के लिए परेश धानाणी का नाम तय माना जा रहा था, परंतु कोली और आहिर नेताओं के इस दौड़ में शामिल होने से फिलहाल मामला खटाई में पड़ गया है।

सेंटरिंग का काम करते समय चौथी मंजिल से गिरे युवक की मौत

सूरत। उधना हीरानगर के युवक की भरत कैंसर अस्पताल के पीछे बिल्डिंग में सेंटरिंग का काम करते समय चौथी मंजिल से गिरने के कारण स्मीमेर अस्पताल में क्षणिक इलाज के बाद मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार डिंडोली के हीरा नगर में रहने वाले अखिलेश सत्यदेव मोहंते (24 वर्ष) बुधवार को भरत कैंसर अस्पताल के पास आरटीएम मार्केट की साइट पर काम कर रहे थे। उसी समय अचानक चौथी मंजिल से गिर गए। जिनके सिर में गंभीर चोट आने से इलाज के लिए स्मीमेर अस्पताल में उनके सेठ बशिष्ठ शुक्ला ने बेहोशी की हालत में भर्ती कराया था। जहां पर क्षणिक इलाज के पश्चात अखिलेश की मौत हो गई। घटना के बारे में पूणा पुलिस माले की जांच कर रही है।

खाद्य सामग्री में घटिया क्वालिटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी: मुख्यमंत्री

गांधीनगर (ईएमएस)। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि जरूरतमंदों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता में मिलावट या घटिया क्वालिटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे गुरुवार को गांधीनगर में गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के सहयोग से १ करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अद्यतन फूड रिसर्च लेबोरेटरी के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरीत होने वाले अनाज और खाद्य पदार्थों की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस अभिनव सोपान का प्रारंभ किया। रूपाणी ने विश्वास जताया कि यह फूड रिसर्च लेबोरेटरी स्टेट ऑफ दी आर्ट स्तर की साबित होगी। देश के अन्य राज्यों तथा विदेशों से भी इस लेबोरेटरी के नवीन प्रयोग को लेकर जिज्ञासा पैदा हुई है। इसके लिए क्वालिटी से कोई समझौता न किया जाए तथा फूड रिसर्च लेबोरेटरी में परीक्षण किया हुआ प्रमाणित खाद्यान्न जत्था ही मिले। उन्होंने भरोसा जताया कि जरूरतमंदों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता में मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए यह लेबोरेटरी एक सक्षम माध्यम साबित होगी। उन्होंने लेबोरेटरी के विभिन्न विभागों में जाकर सभी जरूरी जानकारी हासिल की।

एकीकरण एवं जागरूकता अभियान

ग्रामसभा/वार्ड स्तरीय टीम का गठन

दिन: रविवार,दिनांक: 14 जनवरी-2018, समय: सायं 4:00 -8:00 बजे तक

हमारी आवाज बनेगी,भारत की आवाज

हम मिलकर बनायेंगे अपने,सपनों का भारत-अखंड भारत

हम मिलकर करेंगे, अपनी हर समस्या का समाधान !

आज ही हमसे जुड़ें ! सिर्फ मिस्ड कॉल करें 8076615402

आइये, हम सबमिलकर अखंड भारत की नीव पुन: रखें

सभी क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित हैं !

कार्यक्रम स्थल
ग्रामसभा सिरकिना, सिंगरामऊ-महुली मार्ग
बौद्ध विहार के समीप, बदलापुर,
जौनपुर, उत्तरप्रदेश

सम्पर्कसूत्र
8200090286/ 9891367219
9322986911/ 9819506427

मुख्य अतिथि
मा. आर. पी. द भारतीय
(अखंड भारत)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
PH-9718554504/9891367219

SPYFI-INDIA always with you!

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा तासीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, एवं 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास, सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **Tc.No. : GUJHIN00722**, E-mail: krantisamay@gmail.com